साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 6 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 10 सितंबर 2025 से 16 सितंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, पेड़ों की अवैध कटाई पर उठे सवाल

उत्तरकाशी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर 2025 को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बारिश और बाढ़ से हुई भारी तबाही पर गहरी चिंता जताई है।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे पानी के साथ बहते देखे गए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहली नजर में लगता है कि पहाड़ी इलाकों में अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 8 सितंबर 2025 को हरियाणा के बायल गांव में खदान के आसपास रहने वाले ग्रामीणों और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर खदान से जुड़ी गतिविधियों के पड़ रहे प्रभाव के बारे में संबंधित

अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस मामले में अदालत ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग), खनन और भूविज्ञान निदेशक, महेंद्रगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट, और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे खदान और आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन पेश करें। एनजीटी ने बायल क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खदान द्वारा सीईआर और सीएसआर फंड के रूप में दान दी गई राशि के उपयोग के संबंध में भी जवाब मांगा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को होगी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बायल क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार माइंस अवैध रूप से खनन गतिविधियां चला रही है। खदान साइट और आवासीय क्षेत्र के बीच महज 50 मीटर की दूरी है, जबकि पास में 200 मीटर के भीतर एक स्कूल और अस्पताल भी है। भारी ब्लास्टिंग से आसपास की इमारतों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और हवा में बढ़ता प्रदूषण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। यह भी दावा है कि परियोजना संचालक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) की शर्तों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, खदान की गहराई और सीआएस गतिविधियां। उन्होंने तीन स्टोन क्रशर लगाए हैं, जिनमें से एक बिना कानूनी अनुमति और लाइसेंस के चल रहा है। यह खनन गतिविधियां बायल गांव के खसरा नंबर 198 और 202 में की जा रही हैं, जो अरावली वन क्षेत्र का हिस्सा भी हैं।

बादलों पर इंसानी गतिविधियों का पड़ रहा गहरा असर, आईआईटी मद्रास का खुलासा

मद्रास। पृथ्वी पर इंसानी गतिविधियों का असर अब प्रदूषण या मौसम तक सीमित नहीं है, यह आसमान में बनने वाले बादलों को भी प्रभावित कर रहा है। आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में किए एक नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता चला है कि इंसानी उत्सर्जन हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (एयरोसॉल्स) को गहराई से प्रभावित करता है। गौरतलब है कि यह वही कण हैं जो बादल और बारिश बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। यह अध्ययन भारत के तटीय इलाकों में मार्च से जुलाई 2020 के बीच किया गया और इसमें पाया गया कि हवा में मौजूद यह कण इंसानी गतिविधियों के कारण तेजी से बदलते हैं।

अध्ययन में पाया गया कि खास तौर पर क्लाउड कंडेन्सेशन न्यूक्लिआई (सीसीएन) यानी वे कण जिन पर जलवाष्प जमा होकर बादल बनते हैं, की संख्या लॉकडाउन के बाद 80 से 250 फीसदी तक बढ़ गई। इसका मुख्य कारण था नए कणों का तेजी से बनना। लॉकडाउन के दौरान जब प्रदूषण घटा और फिर धीरे-धीरे इंसानी गतिविधियां शुरू हुईं, तो इंसानी उत्सर्जन के साथ ही नए कण बड़ी मात्रा में बनने लगे और उन्होंने बादलों के बनने की प्रक्रिया

को प्रभावित किया। यह दर्शाता है कि इंसानी गतिविधियां जलवायु प्रणाली पर सीधा असर डालती हैं। लॉकडाउन के बाद साफ समुद्री हवा की जगह प्रदूषित जमीनी हवा का हावी होना बताता है कि मानव गतिविधियों और एयरोसॉल्स का रिश्ता कितना जटिल है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह खोज बेहद अहम है, क्योंकि अब तक जलवायु मॉडल मुख्य रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित रहे हैं। यह अध्ययन असली आंकड़े उपलब्ध कराता है, जो इन मॉडलों को और सटीक बना सकते हैं और भविष्यवाणियों में अनिश्चितता को घटा सकते हैं। इससे मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। शोध में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अब तक जिन जैविक (ऑर्गेनिक) कणों के बारे में माना जाता था कि वो बादल बनने में बाधा डालते हैं, लेकिन शोध से पता चला है कि ये कण कई परिस्थितियों में बादल बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यानी इंसानी उत्सर्जन से उत्पन्न ये कण भी मौसम और जलवायु को बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सच है कि ये कण सतह पर परत बनाकर बूंदों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन दर्शाता है कि जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये बादल बनने में मदद भी करते हैं। अध्ययन में देखा गया कि भारत के तटीय इलाकों में जैविक कणों की बढ़ोतरी से बादल बनाने वाले कण की संख्या बढ़ गई। पानी को आकर्षित करने की क्षमता भले ही इनमें अकार्बनिक कणों से कम हो, लेकिन इनकी भारी संख्या ने बादल बनने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। इसका मतलब है कि जिन्हें हम बादल बनने में बाधक मानते थे, वे भी कुछ परिस्थितियों में बादल और मौसम को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

भोपाल का बड़ा तालाब हो गया फुल, वाटर लेवल पहुंचा 1666.50 फीट

भदभदा डैम के दो गेट खोल बहाया जा रहा पानी

भोपाल ।भोपाल की लाइफ लाइन बड़ा तालाब फुल टैंक लेवल तक भर गया है। इसके बाद शनिवार सुबह 10:35 बजे महापौर मालती राय ने पूजा-अर्चना की और इसके बाद भदभदा डैम के गेट खोले गए। गेट खोलने से पहले साइरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। इसके बाद एक-एक कर दो गेट खोले गए, जिनमें से फिलहाल एक को बंद कर दिया गया है। बता दें पिछले 23 साल में यह दूसरा मौका है, जब सितंबर महीने में भदभदा डैम के गेट खोले गए। इससे पहले वर्ष 2003 में सितंबर में गेट खोले गए थे। वहीं, पिछले साल भारी बारिश के कारण 2 अगस्त को ही गेट खोलने पड़े थे।

एसआई भगवान दास तिवारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से डैम पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम से अतिरिक्त जवान भी बुलाए गए हैं और आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद लोग परिवार सहित डैम के गेट खुलते देखने पहुंच रहे हैं। दरअसल, कैचमेंट एरिया और सीहोर जिले में बारिश होने से बड़ा तालाब का जलस्तर 1666.50 फीट तक पहुंच गया। इसके बाद डैम प्रबंधन ने गेट खोलने का निर्णय लिया। गेट से निकला पानी सीधे कलियासोत डैम में पहुंच रहा है, जिससे वहां भी गेट खोले जाने की संभावना है। वहीं, केरवा डैम में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल जुलाई-अगस्त में ही ये सभी डैम लबालब भर गए थे, लेकिन

इस बार अगस्त सूखा रहा। यही कारण है कि भदभदा, केरवा, कलियासोत और कोलार डैम के गेट अब तक नहीं खोले जा सके थे।

बड़ा तालाब भरने से 2 डैम के खुलते हैं गेट

कोलांस नदी जब उफान पर रहती है तो बड़ा तालाब में पानी जमा होता है। जब बड़ा तालाब पूरा भर जाता है तो भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं। यह पानी सीधे कलियासोत डैम में पहुंचता है। जिससे इस डैम का लेवल भी बढ़ जाता है और फिर इसके गेट भी खुल जाते हैं। बड़ा तालाब को शहर की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसकी वजह यह वाटर लेवल तो बेहतर रखता ही है। साथ में बड़ी आबादी की प्यास भी बुझाता है। बड़ा तालाब से हर दिन पुराने शहर समेत बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर) समेत आसपास के इलाकों की 3 लाख से ज्यादा आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है। 20 प्रतिशत से ज्यादा इलाकों में पानी पहुंचता है। बड़ा तालाब से हर रोज 25 मिलियन गेलन पानी प्रतिदिन) सप्लाई होता है। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1666.80 फीट है।

भोपाल के इन डैमों में इतना पानी

कोलार डैम का वाटर लेवल 1516.40 फीट है। अभी इसमें 1506.82 फीट पानी जमा है। इस हिसाब से यह काफी खाली है। कोलार डैम से ही भोपाल शहर के 40त्न हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती है। पिछली बार जुलाई में इसके गेट खोलने पड़े थे। कुल 1673 फीट वाले केरवा डैम में अब तक करीब 1666.60 फीट पानी आ चुका है। तेज बारिश होने के बाद डैम में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। कलियासोत डैम का अभी वाटर लेवल लगभग 1649.67 फीट है। इसकी कुल जलभराव क्षमता 1659.02 फीट है। इसके चलते डैम अभी भी करीब 9 फीट खाली है। बड़ा तालाब के गेट खुलने पर कलियासोत डैम में पानी आएगा और गेट खुल जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपदा प्रभावित 17500 किसानों के खातों में की 20 करोड़ 60 लाख रूपये की राहत राशि अंतरित

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से प्रदेश के 11 जिलों के 17500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीते दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि (प्राकृतिक आपदा) के कारण फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए इस राहत राशि का हस्तांतरण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जो होना था, हो चुका। हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख-दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर सचिव श्री आलोक सिंह, आयुक्त राजस्व श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी कुशल-क्षेम लेकर फसल क्षति और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी के किसान श्री राघवेन्द्र और श्री जगत पाल, दमोह के श्री सरदार सिंह और श्री संग्राम सिंह, अशोकनगर के श्री प्रदीप सिंह रघुवंशी और कल्याण सिंह, धार के श्री ओमप्रकाश और श्री जगदीश, छतरपुर के श्री रमेश और श्री प्रकाश, रायसेन के श्री अरविंद और श्री अमर सिंह से वर्चुअली संवाद किया। दमोह जिले में पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित रहे। प्रभावित किसानों ने सरकार द्वारा त्वरित रूप से बाढ़ आपदा राहत राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित परिवारों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 24 हजार 884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि का वितरण किया था। राजस्व आयुक्त श्रीमती श्रीवास्तव ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्व पुस्तक में प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रभावित परिवार अपनी आजीविका को पुनर्स्थापित कर सकें। इस मानसून सीजन में प्रदेश में 1031.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 25त्न अधिक है। सर्वाधिक वर्षा गुना में 1603 मिमी,श्योपुर में 1418.6 मिमी, मंडला में 1417.4 मिमी,रायसेन में 1403.2 मिमी और शिवपुरी में 1354.1 मिमी में हुई है।वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए विभिन्न मदों में अबतक कुल 188.52 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी है।

एमपी में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने फीस पर लगाई लगाम

भोपाल मध्यप्रदेश में प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती की जा रही है। स्कूली शिक्षा विभाग ने अनियमित फीस वृद्धि पर लगाम लगाई है। गैर कानूनी वृद्धि को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को फीस के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के फीस विनियमन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। कक्षा वार एवं मद वार आगामी सत्र की प्रस्तावित फीस अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इससे अनियमित फीस वृद्धि की शिकायतों में जबर्दस्त कमी आई है। प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा स्कूलों ने पोर्टल पर फीस विवरण अपलोड किया है। इससे स्कूल शिक्षा शुल्क के संबंध में पारदर्शिता भी बढी है स्कूल शिक्षा विभाग ने फीस में अनियमित वृद्धि रोकने के के लिए स्कूलों को इस संबंध में पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड करने की निर्धारित तिथि भी दी। समय-सीमा में जानकारी अपलोड नहीं करनेवाले स्कूलों के विरूद्ध जिला समिति द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की किताबें, यूनिफॉर्म, टाई एवं कॉपियों पर किसी विशेष दुकान से नहीं खरीदने से संबंधित नियम भी सख्ती से लागू किया है। स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफॉर्म, स्पार्ट्स किट, ट्रासपोर्ट सुविधा और फीस से संग्रहित की जाने वाली राशि का विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तथा अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

बारिश बाद आई याद, शहर को हरभरा बनाने 42 लाख खर्च कर निगम करेगा पौधरोपण

कटनी. शहर को हरभरा बनाने के लिए नगरनिगम ने पौधरोपण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 42 लाख रुपए खर्च कर पौधे लगाने का कार्य कराया जाएगा। नगरनिगम ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया कर दी है, जल्द ही इस कार्य के लिए एजेंसी तय की जाएगी। शहर में डिवाइडर, पार्क, शासकीय कार्यालय व सार्वजनिक स्थलों पर हजारों की संख्या में पौधरोपण किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार नगरनिगम द्वारा पौधरोपण के लिए मियावाकी तकनीक ने पौधे तैयार कराए जाएंगे। मियावाकी तकनीक, पौधा रोपण की एक खास विधि है, जिसमें कम दूरी पर छोटे-छोटे इलाकों में कई तरह के देशी पौधे लगाए जाते हैं। बड़े-बड़े पौधों के बीच में छोटे पौधे लगाए जाते हैं, जो बाद में बड़ा होकर सघन जंगल में विकसित हो जाते हैं। इस तकनीक के तहत नर्सरी में बीज को बोया जाता है और जब बीज अंकुरित हो जाता है और उससे दो पत्ते निकल आते हैं, तब उसे दूसरी जगह लगा दिया जाता है। हालांकि, उन पौधों को तब ढक दिया जाता है, ताकि उसे 60 फीसदी सूर्य की रोशनी से दो महीने तक बचाया जा सके। नगरनिगम द्वारा बारिश के अंतिम दौर में पौधरोपण के लिए टेंडर जारी होने से जानकार सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेशभर और जिलेभर में बारिश के सीजन में पौधरोपण किया जाता है लेकिन नगरनिगम बारिश के बाद पौधरोपण की तैयारी कर रहा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रक्रिया है। पौधे तैयार होने के बाद पौधरोपण कराया जाएगा।

इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का होगा गठन, ईवी मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है मध्यप्रदेश में

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये तैयार हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। जलवायु परविर्तन से लड़ने के वैश्विक जनादेश और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण लक्ष्यों को हासिल करना मध्यप्रदेश की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व ईवी दिवस पर लोगों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। इलेक्ट्रिक वाहन जनसहयोग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में तेजी लाने के लिए सबसे प्रभावी समाधान हैं। मध्यप्रदेश में जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का गठन किया जायेगा। यह अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न मुददों का समाधान निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। मध्यप्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में आदर्श राज्य बनाने और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा। चार्जिंग और स्वैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने में तेजी लाने के प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। प्रदेश में ईवी उदयोग के लिए आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल तैयार करने के लिए नीति में इंजीनयिरिंग कालेजों और आईटीआई में ईवी और ईवी संबंधित पाठयक्रम भी शुरू किये जायेंगे। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में स्थापित किया जायेगा। मध्यप्रदेश का लक्ष्य है कि 2070 तक भारत को अपने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करे और स्वयं को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले राज्यों में पहला स्थान हासिल करे। प्रदेश में वायु गुणवत्ता के सुधार एवं पेट्रोल, डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करने तथा इलेक्ट्रिक चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीरकल नीति-2025 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रदेश में कुल पंजीकृत 02 पहिया, 03 पहिया, चार पहिया वाहन एवं बस के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत के लिए क्रमशः 40%, 80त्न, 15त्न एवं 40त्न का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्ट्रेशन जैसेः- स्माल, मीडियम और लार्ज चार्जिंग स्टेशन के लिए 10 लाख रूपये तक, अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास के लिए 2 करोड़ रूपये, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिये 5 लाख रूपये तक और 02 पहिया, 03 पहिया एवं कार के लिए रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 25 हजार रूपये तक के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थांन भोपाल द्वारा 9 सितंबर को विश्व ईवी दिवस पर लोगों में जागरूकता लाने ईवी कार्यशाला विद्युत 25 और इलेक्ट्रि?क आटो एक्सपो का आयोजन मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल में किया जा रहा है। ईवी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में मध्यप्रदेश अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ईवी सेगमेंट को बढ़ता देख आम लोगों में उत्साह है कि भविष्य में मध्यप्रदेश ईवी मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा। मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता है। यहां सभी प्रकार की सहयोगी अधोसंरचनाएं मौजूद हैं। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी जरूरी है, जिसमें बैटरी निर्माण सुविधाएं, असेंबली प्लांट और सप्लाई चैन नेटवर्क शामिल हैं। मध्यप्रदेश में इसकी भरपूर सभावनाएं हैं। भारत में लिथियम खनन का काफी विकास हुआ है। देश के भीतर लिथियम की उपलब्धता से मौजूदा हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भारत में हाल ही में खोजे गए लिथियम के भंडार से आयात पर निर्भरता में कमी आने के साथ-साथ पूरे ईवी सप्लाई चैन को मजबूती मिलने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा लाभ मध्यप्रदेश को होगा। ईवी का उपयोग न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और उपयोग की लागत को कम करता है बल्कि वितरण दक्षता भी बेहतर बनाता है। प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण के लिए ईवी को अपनाना प्रासंगिक है। मध्यप्रदेश में इसके रूझान दिख रहे हैं। समुदायों और ग्राहकों में जागरूकता बढ़ रही है। भारत दुनिया में दो पहिये वाले वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता हैं। विद्युत वाहन इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ़्टवेयर का मिश्रण है और मध्यप्रदेश का इन दोनों में अच्छा प्रदर्शन है। मध्यप्रदेश में प्रतिभा, अच्छा वातावरण और सरकार के समर्थन से इलेक्ट्रिक वाहन हब बनने को तैयार हो रहा है।

पंजाब बाढ़ - ऊंची सड़कों और जल निकासी के प्राकृतिक रास्तों में अवरोध ने रोका पानी

पंजाब पंजाब की मौजूदा बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि यह मानव निर्मित भी है। इसका एक बड़ा कारण सतही जल प्रवाह में अवरोध है। यही वजह है कि पंजाब के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी ठहर गया है।

जनवरी 2021 में प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट ऑफ द कमिटी कंस्टीट्यूटेड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स इन एनटायर कंट्री एंड रिवर मैनेजमेंट एक्टीविटीज एंड वर्क्स रिलेटेड टू बॉर्डर एरिया (2021-26) के अनुसार, सतही जल निकासी में अवरोध तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक या कृत्रिम निकासी नालियां वर्षा जल के निकास को उचित समय के भीतर वहन करने में सक्षम नहीं होतीं। इसके कारण जलभराव और क्षति होती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समस्या पंजाब के साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक, निकासी सुधार और तटबंध निर्माण से लगभग 20.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से संरक्षित किया जा सका है। पंजाब में प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करने के कई उदाहरण मौजूद हैं। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों को बनाते समय इसकी घोर उपेक्षा हुई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली संसद की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को इस उपेक्षा के लिए 2 सितंबर 2025 को तलब किया था और उनसे दो महीने में उन पुलों और सड़कों की रिपोर्ट मांगी, जिनकी वजह से प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हुआ है। समिति ने एनएचएआई अधिकारियों से राजमार्गों की प्लानिंग रिपोर्ट और जल निकासी की व्यवस्था का ब्यौरा मांगा है। समिति ने पाया है कि ऊंचे हाइवे ने खेतों की प्राकृतिक जल निकासी बाधित की है जिससे किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं और नदियों विकरालता बढ़ी है।

गुरुदासपुर के लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है। उन्होंने डाउन टू अर्थ को बताया कि सिक्खों के धार्मिक स्थल करतारपुर कॉरिडोर सहित गुरदासपुर में बाढ़ की गंभीरता के बढ़ने का एक बड़ा

कारण यह है कि एनएचएआई ने हाइवे पर जल निकासी के लिए कल्वर्ट (पुलिया) नहीं बनाए। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। रंधावा ने कुछ दिन पहले एनएचएआई अधिकारियों को करतारपुर कॉरिडोर की साइट पर बुलाया था ताकि जलजमाव के कारणों का निरीक्षण और समाधान किया जा सके लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। रंधावा ने बताया कि कालाबाड़ी से लेकर चाकावाड़ी गांव तक के 3 किलोमीटर के हिस्से पर हाइवे पर एक भी कल्वर्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर में 3 सितंबर को गवर्नर की मौजूदगी में लोगों ने कहा कि अगर यहां एक कल्वर्ट बना होता तो हम डूबने से बच जाते। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पूरे पंजाब में सड़कें ऊंची हो गई हैं। ऐसे में कल्वर्ट की पहचान की जरूरत है। संसदीय समिति और रंधावा ने जिस विषय को उठाया है, उसी मुद्दे पर 2023 में आई बाढ़ के वक्त जालंधर जिले के गिद्दरपिंडी क्षेत्र में ग्रामीणों ने फ्लड रोकू कमिटी के बैनर तले लोहियां-मक्खू हाइवे जाम कर दिया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि था कि हाइवे पर पुल के गेट बंद होने के कारण सतलुज नदी का पानी उनके गांव में घुस गया है। इसी वर्ष पब्लिक वर्क्स विभाग (पीडब्ल्यूडी) की एक कमिटी ने ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मंडी बोर्ड रोड में ऐसे 346 स्थानों का पता लगाया था जहां जल निकासी का प्रवाह बाधित हुआ था। अलामी पंजाबी संगत के संस्थापक गंगवीर सिंह राठौर एक अन्य अहम मुद्दे की तरह इशारा करते हैं कि पंजाब के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हैं। ऊंचे होने के कारण ये हाइवे एक वाटर वॉल की तरह काम करते हैं, जिससे पंजाब में पानी निकलने में दिक्कत होती है। दिसंबर 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनेलिटिकल रिव्यूज में प्रकाशित पंजाब विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सुच्चा सिंह के अध्ययन पंजाब फ्लड्स- सम लेसन लर्न्ट फॉर फ्यूचर फ्लड मैनेजमेंट में लिखते हैं कि अगस्त 2013 की अत्यधिक वर्षा के दौरान मुक्तसर जिले में नहर नालों के अवरुद्ध हो जाने से 236 गांव जलमग्न हो गए और 1.74 लाख एकड़ फसल क्षेत्र नष्ट हो गया। गंगवीर पंजाब में पानी न निकलने के लिए धान की फसल को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि धान के खेतों में एक कृत्रिम परत बन जाती है, जिससे खेतों के पानी सोखने की दर कम होती है। मॉनसून सीजन में पहले ही से पानी से भरे खेतों में जब बाढ़ का पानी पहुंचा तो स्थिति बदतर हो गई। पंजाब की बाढ़ को भयावह करने में बांधों से अचानक छोड़ा गया पानी भी जिम्मेदार है। स्फेयर इंडिया के प्रोग्राम कॉर्डिनेटर विष्णु पी मानते हैं कि इस साल की आपदा प्राकृतिक और मानवीय कारणों का मिश्रण है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में पंजाब में वर्षा सामान्य से 74 प्रतिशत अधिक रही, जबकि पठानकोट और गुरदासपुर जैसे जिलों में यह 181 प्रतिशत तक ज्यादा दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से आई तेज धारा के कारण ब्यास, रावी और सतलुज नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगीं। विष्णु के अनुसार, ऐसी स्थिति में भाखड़ा और पोंग बांध से आपातकालीन जल छोड़ा गया, जो संरचनाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन अचानक आए पानी ने 1988 जैसी स्थिति पैदा कर दी और रूपनगर, अमृतसर तथा फिरोजपुर में जलभराव को और बढ़ा दिया। रंधावा ने 31 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खत में इस विषय को उठाया है। पत्र के अनुसार, बाढ़ के चरम पर रावी नदी ने अपर बारी दोआब नहर (यूबीडीसी) में लगभग 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। उनका कहना है कि बैराज अब भी औपनिवेशिक दौर के हाथ से संचालित फाटकों पर निर्भर है ।

प्रदूषण व आग बढ़ा रही सांसों की बीमारी

नई दिल्ली। रिपोर्ट के मुताबिक, गंगा के मैदानी इलाकों की धुंध अब सिर्फ मौसम का खेल नहीं रह गई, बल्कि यह इंसानी गतिविधियों से बिगड़ते पर्यावरण का साफ संकेत है वायु गुणवत्ता और जलवायु संकट को अलग-अलग समझने की भूल नहीं की जा सकती; डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा के मैदानों की धुंध और अमेजन के जंगलों की आग से उत्पन्न धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता और जलवायु संकट को अलग-अलग समझने की भूल नहीं की जा सकती 2024 में चीन में नियंत्रण उपायों से इसमें कमी आई है, लेकिन उत्तरी भारत में प्रदूषण के हॉटस्पॉट बने रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, हर साल वायु प्रदूषण से दुनिया में 45 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत हो रही है रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता और जलवायु संकट के आपसी संबंध को उजागर करते हुए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गंगा के मैदानी इलाकों की घनी धुंध हो या अमेजन के जंगलों में लगी आग से उठता धुआं, दोनों ही अब करोड़ों लोगों की सांसों पर सीधा हमला कर रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने अपनी नई रिपोर्ट में साफ कहा है कि वायु गुणवत्ता और जलवायु संकट को अलग-अलग समझने की भूल नहीं की जा सकती। दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं और एक-दूसरे को बढ़ा रहे हैं और इस दुष्चक्र का खामियाजा इंसानी सेहत, कृषि और अर्थव्यवस्था तीनों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि इस समस्या को हल करने के लिए सभी को मिलकर हल करना होगा। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के मौके पर जारी की गई है, जिसे हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या और उससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट में गंगा के मैदानी इलाकों पर मंडराते संकट पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यह मैदानी इलाकों 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को पनाह देता है। यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक है। चिंता की बात यह है कि हाल के वर्षों में यहां वायु प्रदूषण और सर्दियों में होने वाली धुंध (कोहरा) दोनों तेजी से बढ़े हैं। हालांकि यहां पहले सर्दियों में होने वाली धुंध मौसम का हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन अब इसकी बढ़ती अवधि और बार-बार दिखने की वजह प्रदूषण से जुड़ गई है। वाहनों, निर्माण कार्यों, पराली जलाने और घरेलू ईंधन ने इस धुंध को जहरीला बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, अब धुंध सिर्फ मौसम का खेल नहीं रह गई, बल्कि यह इंसानी गतिविधियों से बिगड़ते पर्यावरण का साफ संकेत है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पराली जलाने पर सख्ती की जाए और रसोई, रोशनी, हीटिंग और सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। 2024 में अमेजन के जंगल में लगी भीषण आग से निकले धुंए ने हजारों किलोमीटर दूर बसे शहरों की हवा खराब कर दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008